कोयतुरो की बुलंद आवाज़

कोयतुर टाइम्स

KOYTUR TIMES
www.koyturtimes.com

सुविचार -
समय का उत्तम उपयोग करना सीखें क्योंकि विश्व के ज्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है।

मंगलवार 07 जनवरी 2025 | RNI: UDYAM-CG-11-0005844 | website: koyturtimes.com

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अंतिम प्रकाशन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अंतिम मतदाता सूची की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में बताया कि अंतिम प्रकाशन की फोटोरहित मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर अपलोड कर दी गई है। आम नागरिक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अब राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ 11 लाख पांच हजार 391 हो गई है। इनमें एक करोड़ चार लाख 27 हजार 842 पुरुष मतदाता, एक करोड़ छह लाख 76 हजार 821 महिला मतदाता और 728 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। राज्य में निर्वाचकों का लिंगानुपात (Gender Ratio) 1024 है। उन्होंने बताया कि 18-19 आयु वर्ग समूह में चार लाख 52 हजार 134 मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 24 हजार 371 मतदान केन्द्र हैं। श्रीमती कंगाले ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन एप या वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस, ध्रुव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो और सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रुपेश वर्मा भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने दंतेवाड़ा जाएंगे

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 07 जनवरी को बीजापुर जिले के कुटरू में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री साय सवेरे 9.35 बजे पुलिस लाईन हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 10.50 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद पूर्वान्ह 11.35 बजे कारली पुलिस लाईन हेलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12.55 बजे गरियाबंद जिले के राजिम स्थित कॉलेज ग्राउण्ड स्टेडियम पहुंचेंगे। श्री साय दोपहर 1.35 बजे राजिम में मंदिर दर्शन करेंगे और राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपरान्ह 3 बजे रायपुर लौट आएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने शहीद स्वर्गीय मुकेश शोरी की प्रतिमा का किया अनावरण

रायपुर: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज ग्राम धामनसरा में शहीद स्वर्गीय श्री मुकेश शोरी की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री शोरी ने परिवार और क्षेत्र का मान बढ़ाया है, उनकी स्मृति भावी पीढ़ी और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने शहीद स्वर्गीय श्री मुकेश शोरी के नाम पर स्कूल का नामकरण कराने का आश्वासन दिया। स्वर्गीय मुकेश शोरी ने सीआरपीएफ में सेवा देते हुए जम्मू-कश्मीर, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में कार्य किया। जगदलपुर में सेवा के दौरान तबियत खराब हुई और उनका आकस्मिक निधन हो गया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शहीद के परिवार, जनप्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ने नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने की बात कही।

महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज

रायपुर: नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी को संपादित की जाएगी। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से नगर निगमों में महापौर पद, साढ़े 11 बजे से नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद तथा साढ़े 12 बजे से नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पद की आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।

ब्रेकिंग न्यूज़ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री

हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में कण-कण में प्रभु श्रीराम का वास - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में कण-कण में प्रभु श्रीराम का वास है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला राजिम है और छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाने वाला खरौद भी है। मेरा सौभाग्य था कि जांजगीर-चांपा जिले में माता शबरी की पुण्यभूमि शिवरीनारायण से हम सभी ने भगवान श्रीरामलला के प्राणप्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्रीरामलला की प्राणप्रतिष्ठा के एक वर्ष हो जाएंगे। यह तिथि हम सबके लिए सांस्कृतिक गौरव के सबसे बड़े दिनों में से है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्रीरामलला की प्राणप्रतिष्ठा की तो यह हम सबके लिए बेहद भावुक क्षण था। मोदी जी ने इस अवसर पर दिये अपने संबोधन में माता शबरी को भी नमन किया। भगवान श्रीराम से माता शबरी का स्नेह हम सबको भावविभोर कर देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जांजगीर चांपा जिले में आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस अंचल में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय के लोग भी रहते हैं। जिन्होंने अपने रोम रोम में राम को बसाया है। उन्हें भी प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया था। अयोध्या धाम में श्रीरामलला की प्राणप्रतिष्ठा के बाद जब मैं मंत्रिमंडल सहित रामलला के दर्शन करने पहुंचा तब शिवरीनारायण के बेर भी भेंट किये।

जांजगीर-चाम्पा जिले को दी 183 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

प्रोजेक्ट सक्षम का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री

हमने श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की है, इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के 20 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम, काशीधाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। रेल, सड़क सहित अन्य योजनाओं में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ''मोदी की गारंटी'' पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे दिन हमने आवास से वंचित प्रदेश के 18 लाख लोगों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज बड़ी संख्या में पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं और नए आवास स्वीकृत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने जांजगीर के शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित 57 जोड़ों को नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस अवसर पर 183.41 करोड़ रूपए की लागत के 285 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 118.39 करोड़ की लागत के 112 कार्यों का भूमिपूजन एवं 65.02 करोड़ के 173 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। कार्यक्रम में इन्डस सॉफ्ट कंपनी प्रोजेक्ट संचार अंतर्गत सिद्ध के आईटीआई के साथ निशुल्क टैलीकॉम प्रारंभ करने, आईसीआईसीआई मिशन ड्रीजी सक्षम अंतर्गत 10 शासकीय स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर स्थापना और मेसन ट्रेनिंग हेतु नया ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु ओएमयू किया गया। कार्यक्रम में जिले के पर्यटन कैलेंडर, प्रोजेक्ट सक्षम, विहान समूहों के उत्पाद के लिए ब्रांड नेम बहिनी का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जांजगीर-चाम्पा जिले की ऐतिहासिक पहचान है।

माता शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाये। इस जिले में अधिकांश क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं से सम्पन्न है। यहाँ सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। यह खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्रद्धेय अटल जी छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं और उनके छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बेहतर योजनाओं के साथ सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टोरलेन्स की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया है और महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए उनके खाते में दी जा रही है। हाल ही में महिलाओं को ग्यारहवीं किश्त दी गई है। आदिवासियों के आमदनी का मुख्य जरिया तेंदूपत्ता की पारिश्रमिक दर 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये किया है। कार्यक्रम को लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा के सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री ब्यास कश्यप, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरबंश, श्री बालेश्वर साहू, सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

महासमुंद: श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और हमारा संकल्प है कि-हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सड़क और हवाई कनेक्टीविटी के साथ-साथ कई रेल परियोजनाओं की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक साल में ही मोदी की गारंटी के ज्यादातर कामों को पूरा कर लिया है। सबका साथ-सबका प्रयास और सबका विकास के क्रम में महासमुंद जिले में विकास का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। आने वाले समय में विकास में और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल रहा भरपूर समर्थन : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने 217 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 111 करोड़ रूपये के 335 कार्यों का लोकार्पण और 106 करोड़ रूपये के 84 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में 271 हितग्राहियों को करीब सवा करोड़ रूपये की सामग्रियों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 18 लाख आवास स्वीकृति की गारंटी दी थी। उसे पूरा करते हुए शपथ के दूसरे ही दिन ही हमारी सरकार ने आवासहीन हितग्राहियों के आवास की स्वीकृति दी। अभी साढ़े तीन लाख आवास की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि महासमुंद जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राचीन नगरी सिरपुर और देवाधिदेव भगवान गंधेश्वरनाथ महादेव की ख्याति पूरे देश में है। लक्ष्मण मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की दिशा में हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। इको पर्यटन के क्षेत्र में कोडार जलाशय को विकसित किया जा रहा है। वहीं शिशुपाल पर्वत का सौंदर्यीकरण करने की दिशा में भी काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महासमुंद जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़क बरौंडा चौक महासमुंद से बम्हनी तक सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण का हमने शिलान्यास किया है। अब इस मार्ग पर आवागमन सुलभ होगा। इसी प्रकार महासमुंद से तुमगांव-अछोला मार्ग चौड़ीकरण और सात महतारी सदन निर्माण के लिए भी शिलान्यास हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकारी निरंतर कार्य कर रही है। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ योजना में महासमुंद ने राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है। महासमुंद जिले के कुल 551 ग्राम पंचायतों में से 292 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करके महासमुंद ने छत्तीसगढ़, में प्रथम स्थान हासिल किया है। महासमुंद के हृदय स्थल पर सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण कराया गया है। इस तरह से युवाओं के बौद्धिक और समन्वित विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसान भाईयों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीद रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की जयंती सुशासन दिवस पर गारंटी के अनुरूप हमने किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस का भुगतान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बारिश अच्छी होने के साथ ही फसल भी अच्छी हुई है, इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ कर प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए भेज रही है। अभी तक 20 हजार राम भक्तों को रामलला का दर्शन लाभ मिल चुका है। महतारी वंदन योजना में हम प्रदेश की 70 लाख से अधिक माता और बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए भुगतान कर रहे हैं। महासमुंद जिले की सवा तीन लाख से अधिक माताओं-बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम को सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

बिलासपुर जिले में 264 क्विंटल अवैध धान जब्त

बोदरी: बिलासपुर जिले में कलेक्टर श्री अवनीश शरण के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन प्रक्रिया में व्यापारियों और कोचियों द्वारा अवैध धान खपाने के मामलें में प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। धान का अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज खाद्य, राजस्व, मंडी और मार्कफेड की संयुक्त टीम ने पांच स्थानों पर दबिश देकर 264 क्विंटल धान जब्त किया, जिसकी कीमत 8.18 लाख रुपए आंकी गई है।

तहसील बोदरी के गांव सारधा में संजय किराना से 24 क्विंटल (60 बोरी), तहसील कोटा के सलका नवागांव में दो वाहनों में 300 बोरी धान का अवैध परिवहन करते, गुप्ता ट्रेडर्स परिसर में 200 बोरी धान, ग्राम सीपत मां प्रोविजन स्टोर्स से 24 क्विंटल (60 बोरी) धान जब्त किया गया। तहसील तखतपुर के व्यापारी रामू साहू से 16 क्विंटल धान की जब्ती की गई।

दर्री में 1 करोड़ से 10 कार्य और पोड़ीबहार में 1 करोड़ के सड़क और पुलिया के निर्माण का उद्योग मंत्री ने किया भूमिपूजन

Koytur times

कोरबा: वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा के दर्री जोन के 4 वार्डों में 1 करोड़ की लागत से 10 कार्य, और कोसाबाड़ी जोन के वॉर्ड क्रमांक 29 में सीमेंट क्रांकीट रोड व तीन बॉक्स पुलिया निर्माण का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री देवांगन द्वारा स्वीकृत कराए गए विधायक मद, जिला खनिज न्यास मद, अधोसंरचना मद व 14 वित्त आयोग के कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिन कार्यों की आज नींव रखी गई है, ये सभी वार्डों और मोहल्लों की छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं। जिनकी होने के बाद लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। सामुदायिक भवन बनने से आपको किराए के भवन कार्यक्रम के लिए लेने नहीं पड़ेंगे।मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि पोड़ीबहार खरमोरा स्वागत द्वार के पास कच्ची सड़क हर बारिश में बह जाती थी, कांग्रेस शासन काल में यहां के लोगों को चन्दा कर सड़क बनाना पड़ा था, लेकिन हमने एक वर्ष में ही इस मार्ग के निर्माण और नाले पर पुल के लिए 1.06 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कराई गई। इस मार्ग का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। इस मार्ग के बनने से लोगों को आवागमन में आसानी होगी। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार विकास की सरकार है, समृद्धि की सरकार है, जिससे हर घर और हर वर्ग में खुशहाली आई है।

कोरबा के दर्री जोन के 4 वार्डों में 1 करोड़ की लागत से 10 कार्य का हुआ लोकार्पण

इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेन्द्र देवांगन, मंडल अध्यक्ष ईश्वर साहू, नीरज शर्मा, नारायण ठाकुर, नरेंद्र वाकडे, मनोज लहरे, लक्ष्मण श्रीवास, पार्षद कविता नारायण, मुकुंद कंवर, पार्षद गोलू पांडेय, पार्षद बुधवार साय यादव, पूर्व पार्षद राधे यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष डॉ राजेश राठौर, अनिल वस्त्रकार, एफआर देवांगन, अजय चंद्रा, लक्की नंदा, लिटेश साहू, राजकुमार राठौर सहित अन्य उपस्थित रहे।

इन कार्यों की रखी नींव

दर्री जोन वार्ड क्र. 51 आशानगर बहरापारा में सामुदायिक भवन निर्माण, लागत:15 लाख,वार्ड क्र.51 साथ कालोनी जमनी पाली शिव मंदिर के पास सामुदायिक भवन लागत 1 5 लाख,वार्ड 51 साडा कालोनी जमनीणली कबीर भवन के पीछे सार्वजनिक भवन में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य, लागत 10 लाख, वार्ड 51 कबीर भवन के पीछे साडा कालोनी दर्री सामुदायिक भवन निर्माण, लागत 10 लाख, वार्ड क.52 नीलगिरी बस्ती में मुक्तिधाम शेड का निर्माण कार्य, 5 लाख, वॉर्ड क्र.53 प्रगतिनगर (श्रम नगर) दर्री में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य 10 लाख, वार्ड 55 बलगी के गायत्री मंदिर परिसर के पास सत्संग भवन निर्माण कार्य , 10:00 लाख, वार्ड 55 बल्गीखार जुनापारा में फूलदास घर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 10 लाख,वार्ड क्र 55 में बलगी में कल्वर्ट निर्माण लागत 10 लाख, वार्ड क्र. 55 बल्गी के गुरुघासीदास परिसर जयस्तंभ के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य लागत 5 लाख कुल 1 करोड़ के कार्य,कोसाबाड़ी जोन के पोड़ीबहार वार्ड में सड़क और पुल निर्माण लागत 1.06 करोड़ की लागत के कार्य का भूमिपूजन किया गया।

ब्रेकिंग न्यूज अपेक्स बैंक में नवनियुक्त एम्प्लाइज का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक सुविधा सर्वोपरी: श्री के.एन. कांडे

अपेक्स बैंक द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पंडरी रायपुर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ को आपरेटिव्ह व अपेक्स बैंक के ज्वाइंट कमिश्नर व प्रबंध संचालक श्री के एन कान्डे ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर व अपेक्स बैंक के डीजीएम श्री भूपेश चंद्रवंशी तथा डिप्टी डायरेक्टर व प्रबंधक श्री ए के लहरे उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के एन कान्डे ने नवनियुक्त सहायक प्रबंधको, सामान्य सहायको तथा कार्यालय सहायकों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक सुविधा सर्वोपरी है। छत्तीसगढ़ के किसान सीधे कोआपरेटिव्ह बैंकों तथा पैक्स सोसाइटियों से जुड़े है। किसानों की खेतीगत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कोआपरेटिव्ह बैंको से होती है। कोआपरेटिव्ह बैंको से खरीफ तथा रबी फसलों के अलावा डेयरी, मत्स्य, लाख पालन तथा उद्यानिकी लिए ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जाता है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ में 'सहकार से समृद्धि' की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नवगठित पैक्स सोसाइटी, डेयरी तथा मत्स्य सोसाइटियों का पंजीयन किया जा चुका है। यह समय धान खरीदी का है। किसानों को धान खरीदी की राशि का आनलाइन भुगतान हमारे बैंकों से होता है।

आपरेटिव्ह व अपेक्स बैंक के ज्वाइंट कमिश्नर व प्रबंध संचालक श्री के एन कान्डे ने किया

किसानों को भुगतान में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए साथ ही बैंक के हितग्राहियों व किसानों से यथोचित सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। अपेक्स बैंक के डीजीएम व प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर श्री भूपेश चंद्रवंशी ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रशिक्षण में रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मापदंडों के अनुरूप सामान्य बैंकिंग कार्य व्यवहार, डिपाजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, केवाईसी, कोर बैंकिंग, एटीएम का परिचालन तथा एनईएफटी व आरटीजीएस व आधुनिक बैंकिंग टेक्नालाजी के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नवगठित पैक्स सोसाइटी, डेयरी तथा मत्स्य सोसाइटियों का पंजीयन किया जा चुका

साथ ही बैंक सेवा नियम के तहत नवनियुक्त एम्प्लाइज के पद के अनुरूप कर्तव्यों तथा दायित्वों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के एजीएम श्री एल के चौधरी, एजीएम व अपेक्स बैंक पंडरी के शाखा प्रबंधक श्री अजय भगत, प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक व प्रबंधक श्री ए के लहरे, लेखा अधिकारी श्री प्रभाकर कांत यादव व प्रतिभागीगण उपस्थित थे।

वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य: प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा

रायपुर: धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर राजधानी रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन में देश में एक अग्रणी राज्य है।

आज की कार्यशाला एक शुरुआत है इस कार्यशाला के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एक टॉस्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है इसके माध्यम से ऐक्ट के प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 79 हजार 502 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा 4377 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्राम सभाओं में सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 2081 सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अब व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज भूमि का नामांतरण एवं अन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। अब तक नामांतरण, सीमांकन और त्रुटि सुधार से संबंधित 881 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इससे वंशानुगत रूप से वन भूमि के हस्तांतरण में आ रही कठिनाई को दूर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में वन अधिकार के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनमें मुख्य रूप से वन अधिकारों का डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाइन प्रक्रियाकरण, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एफआरए सेल की भूमिका, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन व्यवस्था का क्रियान्वयन एवं स्टेकहोल्डरर्स की भूमिका, वन अधिकार पत्र धारकों का अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन, ग्राम सभाओं तथा समितियां के क्षमता विकास के माध्यम से सशक्तिकरण आदि प्रमुख हैं। कार्यशाला में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा से प्राप्त सुझावों से वन अधिकार अधिनियम के और बेहतर क्रियान्वयन में यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि कि वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकारों की मान्यता, वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण तथा अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन आदि संपूर्ण कार्यों के बेहतर कियान्वयन हेतु संबंधित शासकीय विभागों तथा अशासकीय संस्थानों की सतत् भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प में वन अधिकार अधिनियम का उचित क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण चरण होगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आदिम जाति विभाग के आयुक्त श्री पी.एस.एल्मा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राजस्व, वन, आदिम जाति तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं को दूर करने पर बल दिया। चौपाल संस्था के श्री गंगाराम पैकरा ने सामुदायिक वन संसाधन के दावों में त्रुटियों को दूर करने और एफआरए क्षेत्र में अनुभवी एनजीओ को मान्य करने का सुझाव दिया। एटीआरईई संस्था से श्री शरद लेले ने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बन गया है। परन्तु केवल सीएफआरआर दावें देना ही काफी नहीं है, अब हमें इसके आगे के चरण पर कर्य करने की जरूरत है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील मिश्रा ने एफआरए के वास्तविव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों के एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। आदिवासी समता मंच की श्रीमती इंदु नेताम ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्राप्त करने में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने का सुझाव दिया। मुख्य वन संरक्षक श्री नबीद ने नवीन वन अधिकार अधिनियम में ग्राम सभाओं को दिए गए व्यापक अधिकारों का उल्लेख करते हुए वन, राजस्व एवं आदिम जाति विभाग को एक साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया । इस हेतु उन्होंने राजस्व विभाग, वन विभाग, आदिम जाति विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से एक साथ मिलकर कार्य करने का आव्हान किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान अंतर्गत 17 मंत्रालयों के सहयोग से भारत सरकार की 25 योजनाओं को सुसंगत तरीके से धरातल पर उतारना है जिसमें वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन अंतर्गत मुख्य रूप से निश्चित समयावधि में वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के मुख्य तत्वाधान में यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सहयोगी संस्थान के रूप में टीआरटीआई, एफईएस (फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी) एवं एटीआरईई (अशोका ट्रस्ट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट) द्वारा भागीदारी की गई। यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा इसे तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के अपर संचालक श्री संजय गौड़ सहित जिलों में पदस्थ सहायक आयुक्त, जिला परियोजना समन्वयक, स्वयं सेवी संस्थाओं और सामुदायिक वनप्रबंधन समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बस्तर क्षेत्र में पर्यटन विकास को मिली गति केशकाल घाटी और टाटामारी में बढ़ रही पर्यटकों की रौनक

संवाददाता | बस्तर

बस्तर क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो गई है और इसका ताजा उदाहरण नेशनल हाईवे 30 पर स्थित केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी को बस्तर की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस घाटी से ही होकर बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों एवं ओड़िसा, आंध्रप्रदेश सहित तेलंगाना तक पहुँचा जाता है। नेशनल हाईवे पर स्थित केशकाल घाटी प्रमुख मार्ग होने के साथ साथ बस्तर क्षेत्र के व्यवसायिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। आज से दो महीने पहले यह घाटी जर्जर स्थिति में थी इस कारण यहाँ से गुजरने वाले लोग धूल एवं लम्बी जाम से परेशान थे। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने घाटी की कायाकल्प के लिए कार्य योजना तैयार किया, फलस्वरूप आज घाटी पूरी तरह से बन कर तैयार है और गाड़ियाँ घाटी से फर्राटे भर रही हैं। केशकाल घाट में मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बीते शुक्रवार को सुबह सभी प्रकार के वाहनों के आवाजाही बहाल हो गई है। घाटी के नवीनीकरण से यातयात में सुगमता आएगी, साथ ही इससे क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। केशकाल घाटी मरम्मत कार्य के साथ-साथ घाटी के दीवारों पर बस्तर की संस्कृति, कला, पर्यटन को चित्रित किया गया है, जिससे घाटी आकर्षण का केंद्र बन गया है। घाटी को अब लोग फूलों की घाटी के नाम के साथ-साथ अब खुबसूरत वॉल पेंटिंग के लिए भी जाना जाएगा। बस्तर में कई खुबसूरत पर्यटन स्थल है और कांकेर जिले के पर्यटन स्थलों को निहारने के बाद पर्यटक घाटी के रास्ते ही आगे की सफ़र तय करते हैं, ऐसे में जब घाटी में बने सुंदर पेंटिंग से उन्हें बस्तर की प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ जिले के शिल्पियों द्वारा बनाए कलाकृति बेलमेटल एवं आदिवासी कला व संस्कृति की महक से पर्यटक रुबरु हो पाएंगे। आप जब घुमावदार मोड़ों वाली घाटी से यात्रा के बाद टाटामारी पहुंचेंगे तब आपकी थोड़ी बढ़ी हुई धड़कने शांत और आँखों को राहत मिलेगी। यहाँ की खुबसूरत नज़ारे देख कर पर्यटकों के मन में काश ये वक्त यही ठहर जाए यह बात आ ही जाती है। और हर कोई यहाँ के नाजरों को अपने मोबाईल में कैद करने से रह नहीं पाते। यही वजह है की इस नूतन वर्ष में पर्यटक दूर-दूर से यहां की नैसर्गिक सुंदरता को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वर्ष 2020 में 20 हजार 950 पर्यटकों की संख्या थी जो अब बढ़कर 01 लाख 76 हजार 682 हो गई है। यहाँ पर्यटकों के रुकने के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है ताकि पर्यटक टाटामारी के साथ-साथ आस पास के अन्य पर्यटन स्थलों तक भी पहुँच सकें। टाटामारी में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल भी रहा है। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर्यटकों को गाँव के पारंपरिक पकवान और भोजन परोसते हैं। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि टाटामारी में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यहां एडवेंचर्स गतिविधियों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। साथ ही पर्यटकों के सुविधाओं की दृष्टि से व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यू पॉइंट, पाथ वे और वुडन कॉटेज के सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और किड्स प्ले गार्डन में सुविधा बढ़ाई जाएगी। साथ ही नए कॉटेज का भी निर्माण किया जाएगा।

घाटी के दीवारों के वॉल पेंटिंग बना आकर्षण का केंद्र

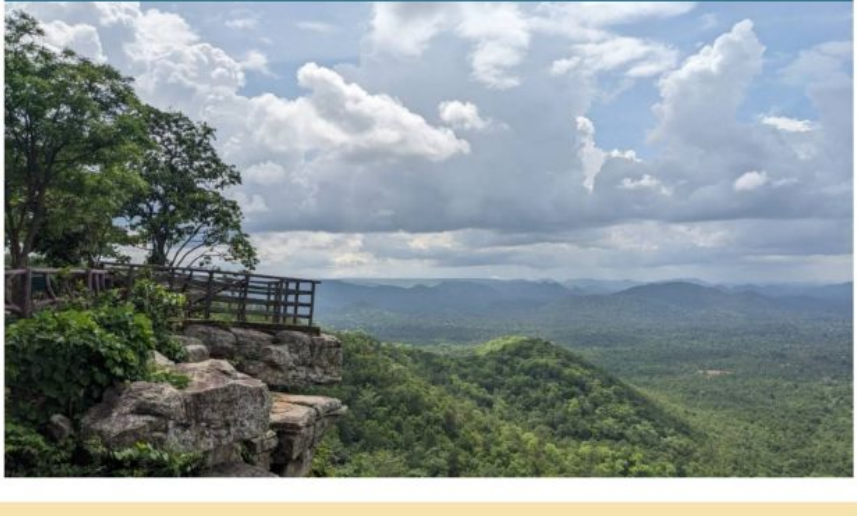

डॉ. मनमोहन सिंह एक सरल और समर्पित देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में दिया अपार योगदान

लेखक/विचारक: महेन्द्र सिंह मरपच्ची

डॉ.मनमोहनसिंहभारतीयराजनीतिकेएकऐसेशख्सियतथे, जिनकीसादगीऔरविद्वताकाप्रभावनसिर्फभारत,बल्किपूरी दुनियापरपड़ा।भारतके13वेंप्रधानमंत्रीकेरूपमेंउन्होंने2004 से2014तकदोकार्यकालोंतकभारतकानेतृत्वकिया।उनके समय में भारत ने आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्णप्रगतिकीऔरउनकीसफलताकीकहानीसंघर्ष,ज्ञान, औरकर्तव्यनिष्ठाकाअद्भुतउदाहरणबनी।डॉ.मनमोहनसिंहका जन्म26सितंबर1932कोअविभाजितभारतकेपंजाबप्रांतके गाहगांव(अबकेपाकिस्तानमें)हुआ।उनकापरिवारसाधारण था,औरशिक्षाकेप्रतिउनकेपिताकागहराआग्रहथा।भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय उनका परिवार भारत आकर अमृतसरमेंबसगया।डॉ.सिंहनेअपनीप्रारंभिकशिक्षाअमृतसर केखालसाहाईस्कूलसेपूरीकी।पढ़ाईमेंवेबचपनसेहीअसाधारण थे।उन्होंने1952मेंपंजाबविश्वविद्यालयसेअर्थशास्त्रमेंस्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद 1954 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्तकीजहांउन्होंनेअर्थशास्त्रमेंडॉक्टरेट(पीएचडी)कीउपाधि हासिलकी।उनकीअसाधारणप्रतिभानेउन्हेंअकादमिकक्षेत्रमें एक स्थान दिलाया और इसके बाद उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें अंतरराष्ट्रीयस्तरपरपहचानदिलाई।उन्होंनेसंयुक्तराष्ट्रकेलिए काम किया और भारतीय सरकार में आर्थिक मामलों के सलाहकार के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1980 के दशकमेंभारतीयरिजर्वबैंककेगवर्नरकेरूपमेंउन्होंनेभारतीय अर्थव्यवस्थाकोस्थिरकरनेकेलिएकईअहमकदमउठाए।

डॉ. मनमोहन सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा और उनके किएगएमहत्वपूर्णकार्य

प्रधानमंत्री बनने के बाद 2013 में उनका छत्तीसगढ़ दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में कई योजनाएंशुरूकी,जिनमेंकिफायतीब्याजदरोंपर ऋण उपलब्ध कराना और कृषि उपकरणों का वितरण शामिल था। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। राज्य में सड़क और परिवहन के विकास के लिए राष्ट्रीयराजमार्गोंकेनिर्माणऔरग्रामीणसड़कोंके सुधार के लिए भी योजनाएं बनाई गई थीं। उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़में राज्यों के अधिकार बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए, ताकि राज्य अपनी विकास योजनाओं को स्वतंत्रता से लागू कर सके और संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जिससे इन क्षेत्रों के लोग रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की ओर अग्रसर हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाएं बनाई गई। छत्तीसगढ़केऔद्योगिकविकासमेंभीडॉ.सिंहका योगदान महत्वपूर्ण रहा। खासकर खनन और इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई औद्योगिकपरियोजनाएंशुरूकियाथा

डॉ. मनोहन सिंह की राजनीतिक शुरुआत के साथ आर्थिकसंकट भीदूरहुआ

डॉ. सिंह ने 1991 में राजनीति में कदम रखा, जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री नियुक्त किया। भारत उस समय एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडारन्यूनतमस्तरपरथा, औरदेशदिवालियाहोने की कगार पर था। डॉ. सिंह ने साहसिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समावेश था। इन नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और देश को तेज़ी से विकास के पथ पर ले गए। उनके इन सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्थाविश्वमंचपरएकप्रमुखशक्तिकेरूप में उभरी। 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उनकी ईमानदारी, सरलता और गहन आर्थिक ज्ञान ने उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बना दिया। उन्होंने 2009 में दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। उनके कार्यकाल में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे तेजीसेबढ़तीअर्थव्यवस्थाओंमेंशामिलहुआ।

डॉ. मनमोहन सिंह की विदेश नीति और वैश्विक संबंधोंमेंरहाअहमभूमिका

डॉ. सिंह ने विदेश नीति के क्षेत्र में भारत-अमेरिका परमाणुसमझौताउनकेकार्यकालकीसबसेबड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। उनके कार्यकाल में विदेश दौरों ने भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. सिंह ने वाशिंगटन डीसी और अन्य अमेरिकी शहरों का दौरा किया, जिसका उद्देश्य भारत को नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करना था। इसके अलावा, G20 सम्मेलनों में भाग लेकर उन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत की भूमिका को मजबूत किया। उन्होंने चीन, जापान, और अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दौरे किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक समस्याओं पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रूस और यूरोपीय संघ के देशों के साथ व्यापार और रक्षा समझौतों को मजबूत किया गया।

शिक्षा और अनुसंधान में डॉ. सिंह का ऐतिहासिक योगदानरहा

डॉ. सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, और शोध के क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में कई ऐतिहासिक पहल की गईं। उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नए संस्थान स्थापित किए, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) शामिल हैं। उनके समय में 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई, जिसने शिक्षा, शोध, और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सुधारकीसिफारिशेंदीं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉ. सिंह का रहा महत्वपूर्ण योगदान

स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉ. सिंह ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की शुरुआत की जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना था। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह मिशन प्रभावी साबित हुआ। इसके अलावा, उन्होंने देश के विभिन्नहिस्सोंमेंछहनएएम्ससंस्थानोंकीस्थापना की और जनऔषधि अभियान की शुरुआत की जिससे सस्ती दवाएं गरीबों तक पहुंच सकी । अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इस दौरान, भारत ने इसरो के माध्यम से चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके कार्यकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे सामाजिक और आर्थिक सुधार भी लागू किए गए, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और मिड-डे मील योजना का विस्तार किया गया, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ और उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयुमेंलीअंतिमसांस

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्तीकरायागयाथा। उन्हें रात 8:06 बजे एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉ. मनमोहन सिंह के जीवन और कार्य ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरी छाप छोड़ी है। उनका योगदान देश की स्थायी प्रगति में हमेशा याद किया जाएगा।

वायु प्रदूषण से निपटने होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर अनिवार्य

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने होलोग्राम आधारित रंग कोड़ वाले स्टीकर को अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 2018 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसमें दिल्ली-एनसीआर इलाके में पेट्रोल- सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले वाहनों में होलोग्राम आधारित अलग- अलग रंग के स्टीकर लगाने की परिकल्पना की गई थी। इनमें वाहन के पंजीकरण की तारीख भी शामिल होनी थी। अदालत के आदेश के बाद केंद्र ने होलोग्राम आधारित स्टीकर की योजना को कानूनी मान्यता देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 50 और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश, 2001 में संशोधन किया। एनसीआर में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए सख्त कदम उठाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। एनसीआर में उप्र, राजस्थान, हरियाणा शामिल हैं। देश में 2022 में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या साढ़े पैंतीस करोड़. के करीब थी, जो इन दो सालों में तीव्र गति से बढ़ी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क होने के कारण परिवहन उत्सर्जन से होने वाला प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये वहान पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के अतिरिक्त मेथनॉल, ईथनॉल, ईंधन सेल हाइड्रोजन, एलएनजी, एलपीजी और सौर से भी चालित हैं। सबके लिए जरूरी है विशेष पहचान। इस स्टीकर के अलग-अलग रंग दूर से इनके ईंधन के संकेतक बन सकेंगे। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंचता है जिसमें सुधार लाने के प्रयास आवश्यक होते जा रहे हैं परंतु बार-बार नये नियम लाद कर जनता से वसूली करना भी सरकारी विभागों की उगाही का जरिया बन चुका है। देश में सबसे बड़ी संख्या दो-पहिया वाहनों की 2.95 लाख बताई जाती है जो सड़क सुरक्षा के साथ ही खराब हवा में सांस लेने को भी मजबूर हैं। प्रदूषणजनित रोगों के अतिरिक्त सड़क हादसों पर लगाम लगाने में सरकारी तंत्र बुरी तरह असफल है। बात भले ही नंबर प्लेट बदलने की हो या किसी तरह के स्टीकर लगाने की, सरकारी स्तर पर ऐसे प्रयास होने चाहिए कि वाहन पंजीकरण के दरम्यान ही इन सबका एकमुश्त शुल्क वसूला जा सके। न कि बार-बार चालान काट कर वाहन चालकों से वसूली चालू की जाए। इससे न सिर्फ जनता परेशान होती है, बल्कि सरकारी संसाधनों और यातायात पुलिस का काम भी बढ़ जाता है। सुविधाओं या नियमों को लागू करने की भी संयमित व्यवस्था जरूरी है।

महिला मुक्ति दिवस पर विशेष लेखः साय सरकार की क्रांतिकारी कदम से छत्तीसगढ़ बढ़ रहा महिला सशक्तिकरण की ओर: महेन्द्र सिंह मरपच्ची

आज के दौर में महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। जब एक महिला को समानता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार मिलता है, तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाती है। यह ''महिला मुक्ति दिवस'' हमें किसी लक्ष्य की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति को मापते हैं, समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता पर विचार करते हैं और उसे दूर करने के लिए नए कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के प्रयासों में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस दिशा में कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिन्होंने राज्य की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हर किसी को दे रहा योगदान

छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं। श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं और नीतियां इस प्रकार हैं: ''शिक्षा और कौशल विकास'' जिसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। बालिका शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि गरीब और वंचित तबके की लड़कियां स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ''सुकन्या समृद्धि योजना'' के अंतर्गत गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो उन्हें स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार करते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए 'महतारी जतन योजना' और 'मुख्यमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण, चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित प्रसव की सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत भी की गई है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में ''महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। पुलिस विभाग में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है, जिससे महिलाएं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ''महिला स्वावलंबन योजना'' और ''दीनदयाल अंत्योदय योजना'' जैसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहित कर महिलाओं को एकजुट किया गया है, जिससे वे सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार की हो रही प्रशंसा

श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उन्होंने न केवल योजनाएं बनाई हैं, बल्कि उनकी प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित की है। इन योजनाओं का लाभ विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मिला है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां सराहनीय हैं । स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनके माध्यम से न केवल महिलाओं की आमदनी बढ़ी है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए, कम है। महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा प्रकोष्ठ ने महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती संख्या राज्य में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई हैं। पर इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। यह महिला मुक्ति दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और क्या कर सकते हैं। यह महिला मुक्ति दिवस न केवल एक पर्व है, बल्कि यह एक अभियान है जो हमें याद दिलाता है कि महिलाओं के बिना समाज अधूरा है। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम किया है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरकार की योजनाओं और नीतियों ने न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के निर्णय लेने की शक्ति भी दी है। आज जब हम महिला मुक्ति दिवस मना रहे हैं, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी स्वतंत्रता, सम्मान और समानता के लिए उठाया गया हर कदम समाज को एक नई दिशा देगा। श्री विष्णुदेव साय की सरकार के प्रयासों के साथ हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बनेगा, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगी और समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी का सघन निरीक्षण आगामी बोर्ड परीक्षा की समीक्षा एवं दिए कड़े निर्देश

एमसीबी, छत्तीसगढ़: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी की सिलसिले में जिले के विभिन्न विद्यालयों शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलबहरा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोगापानी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर का सघन निरीक्षण किया तथा प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ की बैठक ली तथा छमाही परीक्षा के रिजल्ट की समीक्षा की तथा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा परीक्षा तैयारी के संबंध में कड़े निर्देश दिए । सभी विषय शिक्षकों से अलग-अलग चर्चा की साथ ही उन्होंने अन्य विभागीय कार्य परीक्षा पे चर्चा, अपार आईडी, नशा मुक्ति विद्यालय, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति, व छात्रवृत्ति संबंधी कार्यों की समीक्षा की उक्त समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ डॉ विनोद पांडेय प्राचार्य शासकीय स्कूल पिपरिया उपस्थित रहे।

शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में बेहतर कार्य के साथ बलरामपुर-रामानुजगंज जिला विकास की ओर अग्रसर: मंत्री श्री नेताम

बलरामपुर: आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने आज अपने बलरामपुर-रामानुजगंज प्रवास के दूसरे दिन रामानुजगंज में 16 करोड़ 39 लाख से भी अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 123.10 लाख के 20 कार्यों का शिलान्यास एवं 331 लाख की राशि का लोकार्पण शामिल है। मंत्री ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया उनमें खिलाड़ियों की सुविधा हेतु 99.65 लाख की लागत से स्टेडियम निर्माण एवं अधोसंरचना मद अंतर्गत 2 करोड़ 31 लाख रुपए के विभिन्न कार्य शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत 901.60 लाख रुपए की लागत से 28 हाट बाजार निर्माण, (महावीरगंज) में 283.60 लाख रुपए की लागत से 5400 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, कुल 1185.20 लाख की राशि के कार्य का भूमिपूजन किया गया। कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में बेहतर कार्य के साथ बलरामपुर-रामानुजगंज जिला विकास की ओर अग्रसर है। जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मंत्री श्री नेताम ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की सजगता से अपराधिक मामलों में कमी आई है। जिस क्षेत्र में पुलिस और जनता का तालमेल है वहां पर अपराधों में कमी देखने को मिलती है, इसके लिए तालमेल जरूरी है। इसे गंभीरता से लेकर पुलिस का सहयोग अवश्य करें। इस अवसर पर नेताम ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों के दो हितग्राहियों को मुआवजा राशि प्रदान की। वहीं दो हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास शहरी की चाबी सौंपी गई तथा दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। श्री नेताम के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लगाये गए स्टाल का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पुष्पा नेताम, गणमान्य नागरिक ओम प्रकाश जायसवाल, श्री रमन अग्रवाल,अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

कलेक्टर परिसर में कैंटीन संचालन हेतु निविदा 17 जनवरी तक

संवाददाता | एमसीबी

कलेक्टर परिसर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ अंतर्गत कैंटीन हेतु 02 कक्ष, किचन प्लेट फार्म सहित ग्राहकों के लिए हाथ धोने का बेसीन, बर्तन धाने का 01 नग बड़ा बेसीन, नल कनेक्शन, लाईट, पंखा के सुविधा के साथ संचालन हेतु बंद लिफाफा में आवेदन आमंत्रित की जाती है। जो इस सूचना में निर्देशित नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, वे अपनी आवेदन बंद लिफाफा में जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 एवं कार्यालयीन समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर स्थापना शाखा मनेंद्रगढ़ में पंजीकृत डाक, स्पीड़ पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते है। निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालयीन वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in पर अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते है।

ग्राम पंचायत केल्हारी में किया गया जागो मतदाता जागो कार्यक्रम का आयोजन

एमसीबी: जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जागो मतदाता जागो कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में विगत दिवस मनेद्रगढ़ विकासखण्ड ग्राम पंचायत केल्हारी में जागो मतदाता जागो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत ग्राम वासियों को मतदाता शपथ एवं श्रमदान, स्वच्छता भी कराया गया। जागो कार्यक्रम में जिला समन्वय राकेश जैन, प्रभा पयासी, सरपंच, सचित, गंगा राम, भोला सिंह, पीआरपी सुनीता सहित पंच समूह की महिलाएं एवं स्वच्छता ग्राही को विशेष योगदान रहा।

जिले में महात्मा गांधी नरेगा के तहत संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी, 10 जनवरी तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

संवाददाता | मनेंद्रगढ़

एमसीबी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला स्तर पर समन्वयक (तकनीकी), कंप्यूटर प्रोग्रामर और लेखापाल के 01-01 संविदा पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के पत्र क्रमांक/2514/वि-7/स्था/MGNREGA/2024, 08 अक्टूबर 2024 के निर्देशानुसार, जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत उक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदक 16 दिसंबर 2024 को अपराह्न 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच/स्कूटनी जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई, जिसके आधार पर पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची जिले के कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सूचना पटल पर और एमसीबी जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in/notice_category/ भर्ती / पर उपलब्ध है। पात्र/अपात्र सूची के प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थियों को अपनी अपात्रता या किसी त्रुटि पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 10 जनवरी 2025 तक अपने दावा-आपत्ति पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर बंद लिफाफे में कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, द्वितीय तल, कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर कोरिया वृत्त, मनेंद्रगढ़, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा कर सकते हैं।

शासन सहायक शिक्षकों को बर्खास्त न कर अतिशीघ्र खाली पदों में समायोजन का रास्ता निकाले–आर एन ध्रुव

आर.एन. ध्रुव, रायपुर: बस्तर एवं सरगुजा संभाग के तीन हजार बी. एड प्रशिक्षित सहायक शिक्षको के साथ कड़कड़ाती ठंड में कई माताएं छोटे-छोटे दूधमुहे बच्चों को लेकर अपनी सेवा सुरक्षा की मांग की पूर्ति के लिए अंबिकापुर से रायपुर पदयात्रा करते हुए तुता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उनके जायज मांगों का समर्थन करते हुए अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा धरना स्थल पर जाकर समर्थन दिए। इस अवसर पर उन्होंने सहायक शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे जीवन भर तैयारी करने के बाद व्यापम के माध्यम से आप सभी लाखों लोगों में से चयनित होकर आए हैं। कई लोगों ने इस पद में आने के लिए अन्य नौकरियां को छोड़ें, व्यापार व्यवसाय छोड़ें हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टर्मिनेशन आदेश निकालकर आप लोगों को सड़क पर लाकर छोड़ दिए हैं। श्री ध्रुव जी ने कहा की छत्तीसगढ़ में कई हजार शिक्षकों के पद खाली है। शासन से मांग करते हुए कहा कि इन सहायक शिक्षकों को पद से बर्खास्त न कर अतिशीघ्र इन खाली पदों में समायोजन का रास्ता निकालना चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जटगा में प्रसूति महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकार से किया जा रहा वंचित ,मीनू चाट में तीन टाइम नाश्ता लेकिन एक बार नहीं दिया जा रहा है

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जटगा में प्रसव कराने के लिए आने वाले मातृशक्तियों को दे भोजन वितरण सूची में तीन टाइम नाश्ता और दो टाइम भोजन का विवरण का बोर्ड लगाया गया है जो शासन द्वारा प्रसूता महिलाओं को दिया जाता है लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जटगा इसका पालन न करते हुए सिर्फ दो टाइम भोजन दिया जा रहा जबकि प्रसूता महिलाओं को अपने नाश्ता का व्यवस्था खुद से करना पड़ रहा है । अगर जिला प्रशाशन मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करे तो सभी लाभांवित गर्भवती महिलाओं को उनका हक मिल सकता है।शिक्षा के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले भोले भाले लोगों को उनके मूलभूत अधिकार से वंचित न करें।

भलौर,पिपरिया गोंडवाना सांस्कृतिक मैदान को बचाने के लिए कोयापुनेम गोंडवाना महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भलौर/पिपरिया: गोंडवाना सांस्कृतिक मैदान, जो लंबे समय से गोंडवाना समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, को धान उपार्जन केंद्र के रूप में समतलीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इस निर्णय के खिलाफ आज कोयापुनेम गोंडवाना महासभा, एमसीबी (छत्तीसगढ़) के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों और संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में कोयापुनेम गोंडवाना महासभा के पदाधिकारियों के साथ गोंडवाना समय विकास क्रांति आंदोलन के अनुसांगिक संगठन गोंगपा और जीएसयू के सदस्य भी शामिल हुए। उपस्थित ग्रामीणों ने सांस्कृतिक मैदान के संरक्षण की मांग करते हुए कहा कि यह मैदान गोंडवाना समाज की परंपरा और धरोहर का प्रतीक है। इसे किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित करना समाज के अस्तित्व और अस्मिता पर चोट पहुंचाने जैसा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों और संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सांस्कृतिक मैदान को संरक्षित नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि इस फैसले को तुरंत रद्द किया जाए और गोंडवाना सांस्कृतिक मैदान को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखा जाए।

नक्सली हमले में 9 शहीद, फोर्स ने लिया मोर्चा, बस्तर में लाल आतंक के खिलाफ युद्ध तेज

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने अपनी क्रूर और कायराना हरकत को अंजाम देते हुए सुरक्षा बल के जवानों पर बड़ा हमला किया। कुटरू के अम्बेली नाला के पास बारूदी सुरंग विस्फोट के जरिए डीआरजी की टीम के वाहन को निशाना बनाया गया। इस दर्दनाक घटना में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान और एक वाहन चालक वीरगति को प्राप्त हो गए। बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला नक्सलियों की हताशा का प्रतीक है। घायलों और शहीदों की संख्या में वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है।

नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ का निर्णायक अभियान

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहां फोर्स ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक अभियान छेड़ रखा है। सुरक्षाबल नक्सलियों के गढ़ में घुसकर ऑपरेशन चला रहे हैं और हर बार उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। विषम परिस्थितियों और बस्तर की भीषण गर्मी के बावजूद फोर्स का जज्बा और हौसला सराहनीय है। जवानों का एकमात्र लक्ष्य है—बस्तर की खूबसूरत वादियों को 'लाल आतंक' के साये से मुक्त कराना।

नक्सली हमलों के बावजूद जवानों का दिखा साहस

नक्सलियों ने अपने गढ़ को बचाने के लिए बस्तर में सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं, लेकिन हर बार जवानों ने उनका डटकर सामना किया है। इस साल अब तक बस्तर संभाग में 141 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें कई बड़े नक्सली नेता और दुर्दांत कमांडर शामिल हैं। हाल के अभियानों में सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है, जिससे नक्सलियों की ताकत कमजोर हुई है।

16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के माड़ इलाके में देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सलियों में कई टॉप कमांडर शामिल थे, जिन पर लाखों रुपये के इनाम घोषित थे। इसके अलावा, सुरक्षाबलों ने 30 अप्रैल को बूझमाड़ के जंगलों में 10 नक्सलियों को मार गिराया था। इसी तरह मई 2024 में बीजापुर और नारायणपुर के इलाकों में लगातार अभियानों में 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए।

फोर्स के साहसी कदमों से नक्सली डर के साये में सुरक्षाबलों के एक के बाद एक सफल अभियानों ने नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। कई मुठभेड़ों में नक्सलियों के टॉप कमांडर ढेर हुए हैं, जिससे संगठन की शक्ति कमजोर हुई है। बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। सुरक्षाबलों का उद्देश्य है कि बस्तर संभाग को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए।

बस्तर की खूबसूरत वादियां, जो कभी नक्सलियों के खौफ में थीं, अब सुरक्षाबलों के अभियानों से आजादी की ओर बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षाबल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। यह संघर्ष केवल नक्सलियों के खिलाफ नहीं, बल्कि बस्तर की शांति और विकास के लिए भी है। वीरगति को प्राप्त जवानों का बलिदान न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश को प्रेरित करता रहेगा।